ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 576-579

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

चीन–पाकिस्तान गठजोड़ और भारतीय सुरक्षा चिंता

डॉ0 दीप कुमार श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर रक्षा अध्ययन विभाग, एस0 एम0 कालेज चन्दौसी, सम्भल (उ0प्र0) भारत

Received- 04.08.2020,Revised- 09.08.2020, Accepted-11.08.2020 E-mail: - deep_srivastava76@yahoo.com

सारांश : ***वर्तमान समय में चीन, पाकिस्तान के साथ आर्थिक व रणनीतिक सहयोग हेतु दृढ़ है। क्योंकि पाकिस्तान को चीन एक विश्वसनीय सहयोगी स्वीकारता है। दोनों का सहयोगपूर्ण लम्बा इतिहास है, दोनों अपनी सीमाओं का साझा करते है, दोनों के साथ होने से दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव में अड़चनें पैदा होती है। पाकिस्तान हथियारों की विक्री और ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है, प्राकृतिक संसाधनों का भण्डार भी पाकिस्तान में उपलब्ध है और इससे ज्यादें भी कई चीजें है।***

कुंजीभूत शब्द– आर्थिक, रणनीतिक, विश्वसनीय, सहयोगी, स्वीकारता, हथियारों, प्राकृतिक संसाधनों ।

ये रणनीतिक स्थितियाँ बता रही है कि आखिर क्यों चीन प्रोजेक्टों के माध्यम से पाकिस्तान के अन्दर इतनी भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। पाकिस्तान में ज्यादा रूचि लेने के पीछे चीन के अन्य उद्देश्य भी है। संभव है चीन द्वारा ग्वाडर पोर्ट बनाने का केवल आर्थिक कारण न हो बल्कि वह भविष्य में उसे नौ सैनिक अड्डा भी बना सकता हो।

चीन–पाक का रणनीतिक गठजोड़ आने वाले वैश्विक रणनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर बना है। नयी सुरक्षा रणनीति को जाहिर करते हुए अमेरिका ने दिसम्बर 2017 में भारत को मुख्य सुरक्षा पार्टनर घोषित किया और यह भी कहा कि चीन से वैश्विक स्तर पर अमेरिका के हित व प्रभाव में बाधा आ रही है। ट्रम्प 2014 में QUAD प्रस्ताव को दुहराते हुए कहा कि हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में भारत, आस्ट्रेलिया और जापान, अमेरिका के उभरते हुए सहयोगी है। चीन ने भी दूसरा गठजोड़ रूस, उत्तरी कोरिया, सीरिया और पाकिस्तान को मिलाकर बना लिया है। चीन–पाक गठजोड़ के सामने भारत–अमेरिका गठजोड़ भी मजबूती ले रहा हैं।

चीन–पाक के हित में एक दूसरी घटना अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना का वापस जाना है। भविष्य में चीन अपनी पहुँच अफगानिस्तान में भी बनायेगा। वह यह तो स्वतः अफगानिस्तान तक पहुँच बना ले या पाकिस्तान के माध्यम से होकर बनाए। दूसरी स्थिति के लिए उसे पाकिस्तान के साथ और रणनीतिक समझदारी बढ़ानी होगी।

पाकिस्तान में चीन की भू–रणनीतिक योजना–पक्ष एवं विपक्ष –

चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर के व्यापक सकारात्मक पक्ष निम्नवत है –

प्रथमतः पाकिस्तान ऐसे आर्थिक उपायों की तलाश करेगा जिससे पाकिस्तान के सुस्त अर्थव्यवस्था में रतार दिखे। दूसरा पक्ष यह है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर के अंतर्गत ग्वाडर बंदरगाह का निर्माण हुआ। इसके बाद अब चीन चार तरह के युद्धक जलपोत का निर्माण कर रहा है जिससे भारतीय सागर में शक्ति संतुलन साधने में मद्द मिलेगी। इस तरह से चीन में नौ सेना का विस्तार होगा और ग्वाडर बंदरगाह तक चीन की पहुँच भी आसान हो जाएगी। भारतीय सागर में चीन की रणनीतिक रूचि से चीन एक ताकतवर देश के रूप में उभरेगा।

यह चीन की महँगी रणनीति है लेकिन इससे चीन के सामुद्रिक ताकत में विस्तार होगा। ग्वाडर बंदरगाह से न केवल चीन को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि उसे इसका रणनीतिक फायदा भी मिलेगा।

तीसरा पक्ष यह है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर से पाकिस्तान को मौका भी मिलेगा ताकि इसके ढ़ाँचागत परियोजना उन्नत किया जाय। इस ढ़ाँचागत परियोजना में जो उन्नति दिखाई दे रही है, उसमें ग्वाडर–होशाब, खुजडार–बसीमा, कराची लाहौर मोटरवेज, कराकोरम हाईवेज आदि सम्मिलित है।

इससे व्यापार में सुधार परिलक्षित होगा। इससे विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (SEZ) को सृजित करने में मद्द मिलेगी। अगर यह परियोजना संपन्न होती है तो चीन के कई मिलियन डालर की बचत तो होगी ही साथ ही साथ चीन से भारतीय सागर तक की दूरी भी 12000 किमी0 कम हो जाएगी।

चतुर्थ पक्ष यह है कि अत्यधिक चीनी निवेश से अत्यधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध होंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने अनुमान लगाया कि अकेले चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर से 4 लाख रोजगार सृजित होंगे, जबकि अन्य शोधकर्ता संबंधी परियोजनाएँ 7 लाख तक पैदा हो सकती है। पंचम पक्ष यह है कि पर्यटन की संभावनाएँ भी पैदा हो सकती है और होटल उद्योगों को भी इस परियोजना से लाभ मिलने की संभावनाएँ हैं। यदि परिसंरचना में विकास होगा तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा में लाभ मिलेगा।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

पाकिस्तान के लिए चीन की रणनीतिक जिम्मदारी क्यों है ? अमेरिका की दृष्टि में अफगानिस्तान–पाकिस्तान का क्षेत्र आधुनिक समय से सभी महाशक्तियों के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को नियंत्रित करने में 19 वीं व 20 वीं शताब्दी में ब्रिटेन और रूस ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। ब्रिटिश ऐसा मानते है कि वे अपने शासन से आधुनिक पाकिस्तान के आंतरिक क्षेत्र को नियंत्रित रखते थे। उसके बाद 1970 के अन्त में सोवियत संघ इस क्षेत्र में आया जो दशकों तक यहॉ रहने के बाद विशेष कुछ नहीं कर पाया। अन्त में 2001 में अमेरिका पाकिस्तान के सहयोग से वैश्विक आतंकवाद का सफाया करने के लिए इस क्षेत्र में केन्द्रित हुआ परन्तु 18 वर्षों के उसके अभियान मे अपने औपचारिक प्रतिद्वन्द्वियों तालिबान से बातचीत करके वापस चला गया। अब बारी महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश चीन की है कि वह अपना प्रभाव इस क्षेत्र में दिखाये। पाकिस्तान के साथ–साथ पूरे अफगानिस्तान–पाकिस्तान क्षेत्र की स्थिति अत्यंत गंभीर है। यद्यपि 2008 के बाद से पाकिस्तान के अन्दर नागरिक सरकार काम कर रही है लेकिन तब भी पाकिस्तान Garrison State (Notes) बना हुआ है, जिसे चीन समझने में असफल है। इन विषयों को निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है।

(1) चीन का प्रारम्भिक मन्तव्य पाकिस्तान के साथ मिलकर अरब सागर से ग्वाडर तक एक वैकल्पिक समुद्री राह तैयार किया जाए। चीन इसके लिए पाकिस्तान को कर्ज, निवेश और बाजार का लाभ भी देना चाहता है। लेकिन इन मन्तव्यों को पूरा करने के लिए चीन को पाकिस्तान के अन्दर लम्बे समय तक कार्य करना होगा। जिससे तीन प्रकार की चुनौतियॉ सामने आयेंगी।

प्रथम – विभिन्न प्रांतो बलूचिस्तान, गिलगिट–बलरिस्तान और बजरीस्तान के स्थानीय लोग CPEC के चीनी प्रोजेक्ट में अपनी ज्यादा से ज्यादा लाभांस की हिस्सेदारी के लिए माँग करेंगे। पाकिस्तान से ही बराबरी की हिस्सेदारी के लिए कई जगहों पर हिंसा शुरू हो गयी है।

द्वितीय – पाकिस्तान के अन्दर चीन से होने वाला निवेश इतनी ज्यादे कर्ज, ब्याज पर आधारित है कि अन्त में वह पाकिस्तान के अन्दर उथल–पुथल ला देगा। लेकिन पाकिस्तान की नागरिक सरकार व सेना इसके दूरगामी प्रभाव को समझ नहीं पा रहें है। ऐसी ही स्थिति मलेशिया, श्रीलंका और मालद्वीव में हुयी है। मालद्वीव की नयी सरकार ने अपने पूर्व सरकार द्वारा किये गए रेलवे व पाईपलाईन के विलियन डालर के समझौतों को निरस्त कर दिया। श्रीलंका ने 99 वर्षों की करने की एवज में लोन तथा ब्याज जमा करने का बात कर रहा था। पाकिस्तान उन आठ देशों में सम्मिलित है जो चीन के कर्ज से दबे है। पाकिस्तान के अन्दर जितनी हिंसक प्रतिक्रिया दिखायी दे रही है शायद चीन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लम्बे समय तक पाकिस्तान यदि कर्ज से दबा रहा तो यह न केवल CPEC प्रोजेक्ट के लिए नुकसानदेह होगा बल्कि पाकिस्तान की सम्प्रभुता के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। यदि चीन पाकिस्तान का हितैषी है तो उसे पाकिस्तानी सामानों को खरीदना चाहिए, ट्रेड अंसतुलन को दूर करना चाहिए। सरकार व अं0 संगठनों जैसे IMF के साथ मिलकर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। यदि वह पाकिस्तान की संपदा और नयी सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है तो पाकिस्तान निश्चित रूप से कर्ज के जाल में फसेंगा शायद चीन यही चाहता भी है।

तृतीय – चीन द्वारा पाकिस्तान के अन्दर किए जाने वाले निवेश, स्थापना, कर्मचारी और हितों के लिए आवश्यक है कि ईस्लामिक अतिवादियों और आतंकवादी समूहों के ऊपर नियंत्रण लगाकर क्षेत्र में शांति–व्यवस्था स्थापित किया जाए। एक दिन चीन को पाकिस्तान में शांति के लिए विचार करना होगा। पहले पाकिस्तान के अन्दर चीनी नागरिकों को अलगाववादी बलूच और धार्मिक अतिवादी दोनों मिलकर हत्याएँ किया करते थे। 2007 में ईस्लामाबाद के लाल मस्जिद के अन्दर कार्यवायी चीनी सरकार द्वारा पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाने से ही हुआ। अमेरिका पाकिस्तान की ऐसी स्थिति को देखकर निराषा था और ओबामा को एक बार फिर कहना पड़ा कि अफगानिस्तान–पाकिस्तान का क्षेत्र इस धरती पर सबसे खतरनाक जगह है।

भले ही पाकिस्तान अलग प्रकार का दावा करता रहे, बीते वर्षों में चीनी नागरिकों और उसके हितों पर हमले हुए है। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में चीनी सलाहकार के ऊपर 23 नवम्बर 2018 को हमला किया हो। BLA ने इसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार की। BLA के आत्मघाती हमलावरों ने अगस्त 2018 में चीनी इंजिनियरों को पश्चिमी पाकिस्तान के दालबादिन शहर में ले जा रही बस के ऊपर हमला किया। जुलाई 2007 में आतंकवादियों ने तीन चीनी नागरिकों की हत्या की और बलूचिस्तान प्रांत में चीनी कर्मियों को लगातार निशाना बनाते रहे। यह हमले चीनी हितों की सुरक्षा की नाकामी को पाकिस्तान के अन्दर दर्शा रहें है। पहले जब कभी पाकिस्तान ने धार्मिक व अलगाववादी आतंकवादी के विरूद्ध देश भर में कार्यवाई शुरू की तो प्रतिक्रिया स्वरूप चीनी नागरिकों का अपहरण व हत्या की घटनाएँ भी बढ़ी।

भविष्य में पाकिस्तान के अन्दर चीनी संपत्तियों पर होने वाले हमलों से चीन–पाक रिश्तों का परीक्षण होगा ; पाकिस्तान चीन के दबाव में यह आश्वासन दे रहा है कि अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। (Aamir : 2018) वर्तमान में

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

पाकिस्तानी सेना अपने देश के अन्दर चीनी हितों को सुरक्षित रखने के लिए समर्पित है लेकिन इसका अकल्पनीय व्यवहार आतंक विरोध के प्रति अनिश्चितता भविष्य के बारे में कुछ भी दावा नहीं कर सकता। ने अपनी राय रखते हुए कहा कि चीन–पाक के आर्थिक संबंधों में समस्याएँ भविष्य में बढ़ती जायेंगी इसलिए आवश्यक है कि चीन–पाक अपने कार्य पद्धति को नये सिरे से सेट करें।

(2) पाकिस्तान को ज्यादा महत्व देने के पीछे चीन का यह भी मन्तव्य है कि वह पाकिस्तान के माध्यम से जीन–जियांग प्रांत के ईस्लामिक आतंक पर कार्यवाही करना चाहता है लेकिन स्थिति वैसी ही हो सकती है, जिसमें अमेरिका अफगानिस्तान से वापस चला भी गया, लेकिन तालिवानों का समर्थन पाकिस्तान करता रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान के रूढ़िवादी और आतंकी समूह चीन के जीन–जियांग प्रांत के टपहींत मुस्लिमों के साथ मिले हुए है और चीनी हितों को दुष्प्रभावित कर रहें है। चीन के टपहींत मुस्लिमों का सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय से है। टपहींत आतंकियों का लम्बें समय से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों का साथ है और कहीं न कहीं इसमें पाकिस्तानी सरकार का भी सहयेाग है। 1980 से ही टपहींत आतंकी पाकिस्तानी मदरसों में पंजीकृत है और सोवियत संघ तथा बाद में अमेरिकी नेतृत्व के गठबंधन के खिलाु लड़ाई लड़ें है। इन मदरसों में टपहींत लड़ाईओं की भर्त्ती की जाती थी जो बाद जीन जियांग में आकर लड़ाई लड़ते थे।

चीन में Vighar मुस्लिमों पर दबावकारी रणनीति का पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय में आक्रोश था। मार्च 2018 में गिलगिट बाल्टीस्तान के नेताओं ने चीन के जीन जियांग प्रांत के अधिकारियों से मांग की कि तत्काल 50 चीनी महिलाओं को छोड़ा जाए जो पाकिस्तानी पुरूषों से विवाह कर ली है। इनमें से कुछ के ऊपर अतिवादी होने का आरोप लगाकर वर्षों से बंदी बनाकर रखा जा रहा था। कम से कम 120,000 Vighar को कम शिक्षा जेलों में रखा गया था। (The Guradiau 2018) क्या चीन के पैसे और ऋण के माध्यम से पाकिस्तान के धार्मिक रूप से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों से सहानुभूति अर्जित की जा सकती है ?

वास्तव में अमेरिका के वापस चले जाने के बाद अफगान–पाक क्षेत्र के आतंकवादी समूहों में उत्साह आया है ; जिससे चीन के Vighar मुस्लिम का एजेण्डा भी दृढ़ हुआ है। क्या चीन में ऐसी क्षमता है कि वह तालिबान के विचारों में संशोधन करे, उस पर नियंत्रण बना ले या तालिबान व अत्य आतंकी समूहों का नाश कर दे, ये ऐसे कार्य हैं, जिसमें अमेरिका असफल हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प दुखी है कि अमेरिका पाक–अफगान में शांति के लिए अपनी कीमत क्यों अदा करें ? हाल के वर्षों में चीन को आतंकी समूहों द्वारा यह धमकी मिलती है कि वह भी अमेरिका की तरह इस क्षेत्र को छोड़कर चला जाए। चीन अकेले आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, वह पाकिस्तान की स्थिति को नियंत्रित करना चाहता है। (Grossman : 2018) अमेरिकन के चले जाने के बाद इसकी कीमत कौन अदा करेगा? क्या व चीन होगा?

(3) पाकिस्तान की रणनीति सदैव भारत केन्द्रित होती है। जब भी वह बाहरी शक्तियों से राजनीतिक व सैन्य सहयोग स्थापित करता है वह भारत को ध्यान में रखते हुए ही करता है। निःसंदेह पाकिस्तान का 1970 के बाद अमेरिका के साथ रिश्ते इस बात को पुष्ट करते है। चीन का पाकिस्तान में दीर्धकालीन आर्थिक व रणनीतिक हित केवल पाकिस्तान की शांति व स्थायीत्व पर ही निर्भर नहीं है बल्कि स्थायी शांति भारत–पाक संबंधों पर निर्भर है। विशेषज्ञों की मान्यता है कि भारत–पाक के बीच कोई भी गंभीर विवाद चीन के हित में भी नहीं है और ऐसी स्थिति में चीन दोनों में से किसी एक देश का चुनाव कर सकता है और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी दखल इस क्षेत्र में आ जाएगा। इसलिए भारत–पाक के बीच शांति चीन के हित में है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. The Economic Times (2018) China's 'Belt and Road' plan in Pakistan takes a military turn. Eco nomic Times, 21 December, 2018. Available At:// economictimes.indiatimes.com/ articleshow/ 67173327.cms?utm_source= contentofinterest&utm_ medium=text& utm_campaign=cppst.
2. Fair, C. Christine (2017) Pakistan Can't Afford China's 'Friendship'. Froeign Policy, July 3, 2017, Avail able At: httpfroeignpolicy.com/ 2017/07/03/Pakistan-cantafford-chinas-friendship/.
3. David Brewster, Silk Roads and Stringsof Pearls: The Strategic Geography of China's New Path ways in the Indian Ocean, Journal Geopolitics,Vo.22,2017,pp.269-291.

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

5. Aamir, Adnan (2018) Pakistan struggles to contain rise of anti-China sentiment. Nikkei Asian Review, 26 November, 2018. Available At:https://asia.nikkei.com/Spotlight/Belt-and-Road/Pakistan-struggles-to-contain-rise-of-anti-China-sentiment.

6. The Guardian (2018) Chinese crackdown separates Pakistani husbands from Uighur wives. The Guardian, 15 March, 2018. Available At:https://www.theguardian.com/world/2018/mar/15/chinese-crackdown-separates-pakistani-husbands-from-uighur-wives.

*****